

संपादकीय

सार्वजनिक बनाम निजी जिंदगी

राजनेताओं की निजी जिंदगी की वो हद कहां तक है, जिसे सार्वजनिक बहस से अलग रखा जाए, यह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विवादास्पद मुद्दा है। इसलिए कि जिन व्यक्तियों के आचरण से करोड़ों लोगों की जिंदगियां प्रभावित होती हों, उनके कार्य-व्यवहार उनके सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह असंबंधित नहीं रह सकते। इसीलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच निजी जिंदगी को चुनावी चर्चा में लाने के मुद्दे पर छिड़ी बहस में आम जन को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रसंग यह है कि राहुल गांधी ने चुनाव सभा में नरेंद्र मोदी पर सवाल दागा कि उन्होंने अपनी पत्नी जसोदाबेन का उल्लेख उम्मीदवारी के अपने पहले के पंचों में क्यों नहीं किया। तो इस पर अरुण जेटली ने जवाब दिया कि राहुल नरेंद्र मोदी के वैध संबंध के बारे में प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, जब कई कांग्रेसजनों के अवैध रिश्ते हैं। साथ ही जेटली ने कहा कि भारतीय राजनीति में एक अलिखित आचार संहिता है कि नेता एक-दूसरे के परिवार और महिलाओं को विवाद में नहीं घसीटते। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने इस संहिता को तोड़ा है। बहरहाल, मुद्दा यह है कि क्या बड़ी पार्टियों के बीच आपसी सहमति से तैयार ऐसी संहिता होनी चाहिए जिसका लाभ एक-दूसरे के नेताओं को मिलता हो? या जनतंत्र का तकाजा यह है कि सार्वजनिक जीवन में जो भी आए वह अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं को पूरी जांच-पड़ताल के लिए खुला रखे? विकसित लोकतांत्रिक देशों में निजी और सार्वजनिक के बीच फर्क की रखाएं काफी धूमिल हो चुकी हैं। भारत में इस प्रसंग का नाता समाज में महिलाओं के दर्जे से भी है। ताकतवर लोग पत्नी या खुद से संबंधित किसी अन्य महिला को उसका वाजिब हक न दें, इसे आधुनिक समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोकतंत्र के मजबूत होने के साथ भारत में भी नेताओं को हर मामले में जवाबदेह बनाने की आकांक्षा जड़ें जमा रही है। लोग जिन्हें नेतृत्व सीपते हैं, उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वे अपनी जिंदगी और गतिविधियों के बारे में पूरी पारदर्शिता बरतें। इसलिए ‘अलिखित संहिताओं’ पर दर-दर सवाल जरूर उठेंगे। नेता सार्वजनिक जीवन में स्वेच्छा से आते हैं। मगर यहां आने के बाद उन्हें जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक ही आचरण व व्यवहार करना चाहिए।

बात पते की

यदि हम संयुक्त, एकीकृत, आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शांस्त्रों की सम्मभुता का अंत होना चाहिए।
 -डॉ. भीमराव आंबेडकर

जीने की राह

कई लोग वक्ताओं से सवाल पूछते हैं कि मंच से उतरकर उन्हें कैसा लगता है। अच्छे वक्ता के साथ उस समय दो संभावनाएं होती हैं। अपने कहे हुए के प्रति संतोष और प्रशंसा का अहंकार। यह स्थिति कलाकार के साथ भी होती है। इसे थोड़ा अध्यात्मिक दृष्टि से देखें। सांसारिक दृष्टिकोण से मंच परीक्षा स्थल जैसा होता है। आप पास या फेल हो सकते हैं। आध्यात्मिक धरातल पर यही मंच व्यासपीठ में बदल जाता है। प्रवचनकारों व कथावाचकों के लिए व्यासपीठ मां की गोद से कम नहीं होता। वैसे वे बिस्कुल सामान्य आदमी होते हैं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठते ही शक्तिपात होता है। अगर वक्ता ईमानदार, चरित्रवान और साधक है तो फिर उसके भीतर कोई और शक्ति बैठकर



मुद्दा

पिछले पांच चुनावों में युवाओं ने एक वर्ग के रूप में मतदान नहीं किया, वह धर्म, जाति, क्षेत्र में ही बंटा रहा है

बहुत अहम नहीं है युवा वोटर

इस बात पर तो कोई विवाद नहीं है कि इस बार के आम चुनाव में युवा मतदाताओं (18 से 25 वर्ष आयु) की संख्या बहुत ज्यादा है। हाल के अनुमानों के मुताबिक युवा मतदाताओं की संख्या 2009 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले कुल वोटों की तुलना में बहुत ज्यादा है। यह वाकई बहुत बड़ा फर्क है। युवा मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में लगभग सभी राजनीतिक दल इन्हें अपने पक्ष में करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर उस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव में हार या जीत में इन्हें मतदाताओं के वोट निर्णायक साबित होंगे। हालांकि, ऐसा सोचने वाले नेता और राजनीतिक दल गलतफहमी में हैं। जो राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत के लिए युवा मतदाताओं या पहली बार वोट देने वालों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, अपने प्रचार को उन्हीं पर केंद्रित किए हुए हैं, हो सकता है कि उन्हें इसका उलटा ही खमियाजा भुगतना पड़े।

इसकी वजह यह है कि भारतीय युवा शायद ही कभी ‘युवा’ मतदाता की तरह एक वर्ग के रूप में मतदान करता है। अन्य भारतीय मतदाताओं की तरह हमारा युवा मतदाता भी जाति, वर्ग, क्षेत्र और धर्म जैसी एकाधिक पहचानों में उलझ जाता है। फिर जेंडर और उम्र की अलग पहचान तो है ही। कहना होगा कि भारतीय वोटर की जाति व वर्ग की पहचान अन्य पहचानों से बहुत ज्यादा मजबूत है। कुछ हद तक धर्म और क्षेत्र की पहचान भी अस्पर डालती है। इसलिए जब युवा वोट देते हैं तो अपनी उम्र या बेरोजगारी व महंगी होती उच्च शिक्षा जैसे चिंता के अन्य मुद्दों पर एकजुट होने की बजाए अन्य पहचानों के आधार पर वोट डालता है। इस प्रकार उनके मतों का विभाजन हो जाता है, जैसा कि अन्य समूहों का होता है।

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) द्वारा पिछले कई वर्षों में कराए गए अध्ययन से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि जेंडर या उम्र के आधार पर भारतीय मतदाता की पहचान (युवाओं में भी) बहुत कमजोर है। यानी यह पहचान अन्य पहचानों के सामने अस्सर नहीं डाल पाती। हमें ऐसा कोई आम चुनाव नजर नहीं आया, जिसमें देश के युवाओं ने ‘युवा वर्ग’ की तरह या जवान मतदाताओं



के एक समूह के रूप की तरह मतदान किया हो। अध्ययन से संकेत मिलता है कि युवा वर्ग ने कभी किसी राजनीतिक दल के पक्ष में थोकबंद मतदान नहीं किया। कम से कम पिछले पांच लोकसभा चुनावों (1996, 1998, 1999, 2004 और 2009) में तो नहीं। अन्य किसी आयु वर्ग वाले मतदाताओं की तरह वे भी विभिन्न राजनीतिक दलों में बंटे हुए पाए गए। दलों के लिए उनकी प्राथमिकताएं अलग थीं। दो राजनीतिक दलों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को उनके राष्ट्रीय औसत के अनुसार लगभग समान अनुपात में युवाओं के वोट मिले। 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को युवाओं के वोट अधिक संख्या में मिले। राजनीति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों के साथ मिलकर युवा वोटों के कारण भाजपा को सबसे अधिक संख्या में लोकसभा सीटें जीतने में मदद मिली। हालांकि, ऐसा लगता है कि बाद के चुनाव में भाजपा युवाओं का यह समर्थन खो बेठी।

भारत जैसे भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र जैसी व्यापक विविधता वाले भौगोलिक रूप से विशाल देश में स्थानीय मुद्दे या उम्मीदवार की जाति का मुद्दा या अन्य पहचान राजनीतिक सक्रियता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। युवा न सिर्फ इस मांबिलाइजेशन प्रक्रिया का हिस्सा हो जाता है बल्कि वह मतदान करते समय इन मुद्दों पर विभाजित भी हो जाता है। इससे कई लोगों को कोई आप्रचर्य नहीं होगा, क्योंकि इससे यह तथ्य सामने आता है कि विभिन्न दल किस तरह की राजनीति करते हैं।

विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों, कार्यक्रमों और घोषणा-पत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो पाएंगे कि मुश्किल से ही कोई ऐसा दल है जो भारतीय युवा की चिंता के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देता हो। उनमें वादे भले ही हों, पर कोई ठोस कार्यक्रम नजर नहीं आता। यहां तक कि युवाओं का थोड़ा ज्यादा समर्थन हासिल करने वाले वाम विचारधारा के राजनीतिक दल भी

जीवन दर्शन

भारत के महान समाज सुधारक और आधुनिक भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर को अपनी बाल्यावस्था से ही सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। तब भारतीय समाज में छुआछूत का बड़ा बोलबाला था। वे इससे बहुत दु:खी हो जाते थे और मन में संकल्प करते थे कि एक दिन वे इस व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। उनके इस संकल्प को मजबूत करने वाली एक घटना उनके बचपन में घटी। एक दिन तेज धूप में विद्यालय से घर लौटते समय उन्हें प्यास लगी। रास्ते में कुछा देखकर उसमें से पानी निकाला और हाथ-मुंह धोकर पानी पीने लगे। तभी एक व्यक्ति उन्हें देखकर चिल्लाया, ‘ तूने कुएं से पानी क्यों पीया? प्यास लगी थी, तो मांगकर नहीं पी सकता था!’ उसकी चीख-पुकार से आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए। माजरा समझ में आते ही सभी ने बालक आंबेडकर को डांटना व कोसना शुरू कर

दिया, ‘इसने तो कुआं ही अशुद्ध कर दिया। इसे तो कुएं का पानी पीने का अधिकार ही नहीं है।’ यह कहते हुए लोगों ने आंबेडकर को पीटना शुरू कर दिया। सभी कह रहे थे कि इसे इतना मारो कि फिर कभी ऐसा काम करने की हिम्मत न करे। आंबेडकर को सभी ने मिलकर अत्यंत क्रूरतापूर्वक मारा। जब वे रोते हुए घर आए तो परिवारजन पूरी घटना सुनकर भी चुप रहे। बड़े भाई यही बोले, ‘अब ऐसी गलती कभी न करना। हमें कुएं पर जाने का अधिकार नहीं है।’ तभी से आंबेडकर का संकल्प और दृढ़ हुआ। बरसों बाद उन्हीं के प्रयासों से बंबई लेजिस्लेटिव असेंबली ने यह बिल पास किया कि सारे जलस्रोत सार्वजनिक प्रयोग के लिए हैं, उन पर किसी व्यक्ति या जाति विशेष का हक नहीं है। रुढ़ियों, अंधश्रद्धा का ही दूसरा रूप है, जो सामाजिक विकास में बाधक हैं। समाज को रूढ़ि मुक्त करने का कार्य दृढ़ संकल्प वाले ही कर सकते हैं।

नेत की दुनिया पर उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कंटेंट एक जगह वेब भास्कर में...

Web Bhaskar

डॉ. आंबेडकर ने पूरा किया संकल्प

23 लाख पत्थर लगे थे निर्माण में

- विश्व के सात अजूबों में गीजा का पिरामिड सबसे अधिक पुराना है।
- तीन पिरामिडों में ग्रेट पिरामिड ही सबसे बड़ा और अब तक का विशालतम है।
- इसके निर्माण में पत्थर के करीब 23 लाख टुकड़े लगे थे। हर पत्थर का वजन ढाई टन से 15 टन तक था।
- प्राचीन काल में इस पूरे इलाके को खुरफु की सीमा के तौर पर जाना जाता था।
- यह एकमात्र ऐसा पिरामिड है, जिसमें आप नीचे से ऊपर की ओर और वहां से फिर नीचे आ सकते हैं।
- इस पिरामिड का दरवाजा कुंडियों वाला है, जिसका वजन 20 टन है। अंदर से ही उसे आसानी से खोला जा सकता है। बाहर से इसे रिव्सकाना भी सुवि्कल है क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह फिट है।
- आसपास दो अन्य पिरामिड हैं। उनमें एक खुरफु के पिता और दूसरा उनके दादा का है।
- ग्रेट पिरामिड को बनाने में मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था, जो आज किसी भी तरह संभव नहीं है।
- विशेषज्ञों ने इसकी तरह छोटा रूप भी बनाने की कोशिशें कीं, लेकिन विफल रहे।
- वैश्विक स्तर की फर्सर् भी मान चुकी हैं कि मिस्त्र में उस दौर की टेक्नोलॉजी अद्भुत थी, आज इसकी प्रतिकृति भी संभव नहीं।

•ancientworldwonders.com

सरप्राइजिंग

मलेशियाई आर्टिस्ट ने 64 हजार चॉपस्टिक से बनाई जैकी चैन की कलात्मक तस्वीर

हांगकांग मूल के मशहूर अभिनेता जैकी चैन को दुनियाभर से उपहार मिल चुके हैं। हाल के दिनों में उन्हें एक मलेशियाई फैन ने चॉपस्टिक (चीनी कांटा) से बनी उनकी तस्वीर भेंट की है। उनकी पहले भी हाथ से बनी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन उनमें कलर पेंट का इस्तेमाल किया गया था। कुछ अलग कर दिखाने के लिए मशहूर मलेशियाई कलाकार रेड होंग यी ने इस बार भी यही किया। वे खुद को ब्रशलेस पेंटर कहती हैं। उन्होंने इस बार 64 हजार डिस्पोजेबल चॉपस्टिक एकत्र की और बनाने लगीं मार्शल आर्ट स्टार जैकी चैन की तस्वीर। चॉपस्टिक



के इस्तेमाल पर यी ने कहा कि यह चीनी संस्कृति का हिस्सा है। यी ने सफलतापूर्वक जैकी चैन की तस्वीर बना ली।

•boomsbeat.com

करंट अफेयर्स

भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में वादा किया है कि वह सत्ता में आई तो भारत का एटमी सिद्धांत बदल देगी? क्या इसे बदलने भर से ही हमारा देश सॉफ्ट स्टेट की छवि से मुक्त होकर महाशक्ति बन जाएगा।

एटमी सिद्धांत बदलने से क्या हासिल होगा?



■ रहीश सिंह

भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि यदि वह सत्ता में आती है तो वह भारत के परमाणु सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन करेगी और इसे संशोधित करेगी ताकि इसे मौजूदा चुनौतियों के लिए प्रासंगिक बनाया जा सके। इसका मतलब कहीं यह तो नहीं कि भारत अब ‘नो फर्स्ट यूज’ के नाभिकीय सिद्धांत को त्याग देगा? अगर यह मानें कि पाकिस्तान जैसा देश जब ‘नो फर्स्ट यूज’ के सिद्धांत को नहीं मानता तो दुनिया को भारत से भी इसके प्रति प्रतिबद्ध होने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए? तो क्या यह मान्यता उचित होगी? हम पाकिस्तान को एक उद्बुद्ध और अराजक राज्य की श्रेणी में रखते रहे हैं, तो इसकी एक वजह यह भी है। अब यदि हम भी यही करें तो क्या देश की छवि पर विपरीत परिणाम नहीं पड़ेगा? क्या केवल एटमी शक्ति के प्रयोग का सिद्धांत बदल देने मात्र से ही भारत सॉफ्ट स्टेट से महाशक्ति में रूपांतरित हो जाएगा?

यदि ऐसा हुआ तो चीन और पाकिस्तान एक तरफ हमारे खिलाफ आक्रामकता अपनाएंगे और दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर भारत का कूटनीतिक घेराव करेंगे। विश्व शक्तियों के साथ कूटनीतिक संबंधों का भावी खाका क्या होगा? क्या अपने फेरसले से जुड़े इन सारे पहलुओं पर पार्टी ने विचार कर लिया है? पोकरण-2 के बाद अगस्त 1999 में भारत ने अपने एटमी सिद्धांत का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसमें ‘नाभिकीय संशर्षों का पहले प्रयोग नहीं’ और ‘विश्वसनीय न्यूनतम निवारण’ के सिद्धांत को मान्यता दी गई। इसके तीन अंग हैं- नो फर्स्ट यूज, मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस और डिसआर्मामेंट। इससे अपनी छवि सुधारकर पीछे के दरवाजे से ही सही, भारत वैश्विक एटामिक बिरादरी में शामिल हो गया।

हालांकि, ऐसा नहीं है कि भारत के ‘नो फर्स्ट यूज’ सिद्धांत से पीछे हटते ही दुनिया में नाभिकीय होड़ शुरू हो जाएगी। वह तो पहले से ही चल रही है। पाकिस्तान के पास ही 100 से अधिक एटमी हथियार हैं। जबकि दुनिया में लगभग 19,000 (स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक) अथवा 23,375 (फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट) परमाणु हथियार इकट्ठे हो गए हैं, जो दुनिया को तबाह करने के लिए काफी हैं। ऐसे में भारत को अपने सामरिक हितों को देखते हुए प्रभावशाली, भरोसेमंद प्रतिरोध तथा पनास जवाबी क्षमता की आवश्यकता है और यह यूएन चार्टर तथा अमेरिकी सम्प्रभुता सिद्धांत के अनुरूप है। उल्टेखनीय है कि जवाबी क्षमता के रक्षागारों की रक्षा करना ही नहीं है, बाहरी चुनौतियों, खासकर नाभिकीय चुनौतियों का प्रतिरोध करना भी इसमें शामिल है।

बहरहाल, दुनिया में नाभिकीय होड़ को देखते हुए भाजपा नेतृत्व यह कह सकता है कि उसके लिए वही सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रासंगिक है जिसे हेनरी किंजिंजर ने इन शब्दों में व्यक्त किया था, ‘शांति कोई नैसर्गिक विधान नहीं है। शांति और सुखशा भगवान भरोसे नहीं छोड़े जा सकते।’ लेकिन इस तरह का कदम उठाने से पहले उसे भारत की आंतरिक स्थितियों, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों, वैश्विक संबंधों की जरूरतों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए था, जो शायद उसने नहीं किया। तैत्तक विदेश व आर्थिक मामलों के जानकार हैं।

raheessingh@gmail.com

नॉलेज



पर्सनल रॉकेट और सिमुलेटर्स बनाने के लिए नासा जारी करेगी सीक्रेट कोड्स

स्पेस साइंस

45 साल पहले नासा का अपोलो-11 यान चंद्रमा पर उतर था। उसके सिस्टम को संचालित करने के लिए एक सीक्रेट कोड था, जो अब तक नासा के ही पास था। हालांकि अब नासा अपने ऐसे सिस्टम्स के कोड्स जनता को मुहैया करा रहा है। इससे यह होगा कि अगर कोई व्यक्ति खुद रॉकेट बनाना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकेगा। नासा ने ऐसे कई सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स के कोड आम जनता के लिए मुहैया करा दिए हैं। इसमें अपोलो-11



16 जुलाई 1969 को जब सेटर्न वी रॉकेट अपोलो 11 यान को लेकर लिफ्ट ऑफ हो रहा था, तब नासा के लॉन्च कंट्रोल सेंटर का ऐसा था दृश्य।

का पासवर्ड भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति उस प्रोग्राम और उसके पासवर्ड को डाउनलोड करके रन कर सकेगा। उसके लिए कोई राशि भी चुकानी नहीं पड़ेगी। इतना ही

•afterdawn.com

दिवतर

हम आजाद हुए 1947 में, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में शिवा का अधिकार मूल अधिकार माना। कानून बना 2009 में। हर चीज के लिए हमारे यहां कानून ही हैं, पालन होना न होना अलग बात है।

-अजय पाल नागर, ग्रेटर नोएडा

किताब में कही बात काफी हद तक सही भी है। केंद्रीय मंत्री अपनी फाउल्लों को पीएम दफ्तर भेजने से पहले मुहर लगवाने गुजरात के एक नेता के घर जाते थे।

-अलका लांबा, ‘आप’ नेता

सालों बीत गए पर देश में अब तक शिवा और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी बातें ही मुद्दा बनी हुई हैं। न जे जरूरतें पूरी हुई हैं न जे (कुछ नेता) कभी होने देंगे।

-मनोज यादव, वाराणसी

हमारी मुद्रा का अवमूल्यन व देश के सवा करोड़ नागरिकों की वैश्विक प्रतिष्ठा में गिरावट, हमारी अर्थव्यवस्था की विफलता नहीं तो क्या है?

-भारत वसन्तमान, हरिद्वार

संजय बारू की पुस्तक ‘द एक्सिस्टेंटल प्राइम मिनिस्टर’ में कितना सच है, यह तो बाद में पता चलेगा। यह पुस्तक बेस्ट सेलर जरूर बन जाएगी। यह तय है।

-विन्दु शर्मा

देश के विकास में कभी किसानों की भागीदारी नहीं बताई जाती। हकीकत में किसानों ने पिछले कुछ समय में पैदावार बढ़ाकर देश के विकास में योगदान दिया है।

-गीरव कुमार सहाय, बिहार

सलमान खान को दिवतर पर चार साल हो गए हैं और देग भी चल पड़ा। यह दिवतर पर अब तक का सबसे घटिया ट्रेंड है, जो दिख रहा है।

-प्रथमेश फिरंगी

नेशनल आइडिशन न्यूज़मैन